



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 354]
No. 354]नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 14, 2012/आषाढ़ 23, 1934
NEW DELHI, SATURDAY, JULY 14, 2012/ASADHA 23, 1934

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2012

सा.का.नि. 561(अ).— केन्द्रीय सरकार ने हाँगकाँग को 1 दिसंबर, 1968 से एक व्यतिकारी राज्यक्षेत्र घोषित किया था और उच्चतम न्यायालय, विकटोरिया जिला न्यायालय, कोलून जिला न्यायालय और हाँगकाँग के फन्टिंग जिला न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 44क के प्रयोजन के लिए भारत सरकार के तत्कालीन विधि मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 2096, तारीख 18 नवंबर, 1968 द्वारा वरिष्ठ न्यायालय घोषित किया था ;

और चीन जनवादी गणतंत्र ने 1 जुलाई, 1997 से हाँगकाँग पर संप्रभुता का पुनरारंभ करने पर ग्रेट ब्रिटेन के युनाइटेड किंगडम और उत्तरी आयरलैंड तथा चीन जनवादी गणतंत्र की सरकार के बीच हाँगकाँग के प्रश्न पर विजिंग में 19 दिसंबर, 1984 को हस्ताक्षरित संयुक्त घोषणा में चीन जनवादी गणतंत्र के हाँगकाँग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र को स्थापित किया है ;

और उक्त घोषणा, अन्य बातों के साथ-साथ, चीन जनवादी गणतंत्र की हाँगकाँग के संबंध में मूल नीति का कथन और उक्त घोषणा के उपाबंध 1 में उनका विस्तार करती है जिसे हाँगकाँग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र की मूल विधि में शामिल किया गया है ;

और हाँगकाँग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र की स्थापना के पश्चात् उस क्षेत्र में स्वतंत्र न्यायिक शक्ति को हाँगकाँग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के न्यायालयों में और अन्तिम निर्णय की शक्ति को अंतिम अपील न्यायालय (उक्त घोषणा के उपाबंध का भाग-3) में विहित किया गया है ;

और अंतर्राष्ट्रीय समझौते, जिनमें चीन जनवादी गणतंत्र एक पक्षकार नहीं है किंतु जिन्हें हाँगकाँग में कार्यान्वित किया गया था, का हाँगकाँग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (उक्त घोषणा के उपाबंध का भाग-9) में कार्यान्वित किया जाना जारी रह सकेगा ;

और भारत सरकार, हाँगकाँग के चीन जनवादी गणतंत्र को प्रत्यावर्तन और तत्पश्चात् हाँगकाँग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र की स्थापना के पश्चात् भारत और हाँगकाँग के बीच व्यतिकारी निर्णय के प्रवर्तन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 44 के अधीन विद्यमान प्रबंध को बनाए रखती है ;

और हाँगकाँग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र की स्थापना और हाँगकाँग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के वरिष्ठ न्यायालयों के नाम में परिवर्तन के पश्चात् हाँगकाँग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र को 1 जुलाई, 1997 से व्यतिकारी राज्यक्षेत्र घोषित करने के लिए और हाँगकाँग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के न्यायालयों की नई संरचना को हाँगकाँग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के वरिष्ठ न्यायालयों के निर्णयों के भारत में प्रवर्तन को सुकर बनाने के लिए उक्त अधिसूचना का संशोधन करना समीचीन हो गया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 44क के स्पष्टीकरण 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन विधि मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) की अधिसूचना सं. 2096 तारीख 18 नवम्बर, 1968 को उन बातों के सिवाए जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई हैं या जिनके किए जाने का लोप किया गया है, अधिकांत करते हुए, 1 जुलाई, 1997 को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए हाँगकाँग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र को व्यतिकारी राज्यक्षेत्र और हाँगकाँग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में निम्नलिखित न्यायालयों को उस राज्यक्षेत्र के वरिष्ठ न्यायालय घोषित करती है, अर्थात् :-

1. अंतिम अपील न्यायालय (हाँगकाँग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में उच्चतम अपीलीय न्यायालय),
2. अपील न्यायालय सहित उच्च न्यायालय और प्रथमतः न्यायालय, और
3. जिला न्यायालय,

स्पष्टीकारक ज्ञापन : इस अधिसूचना की प्रस्तावना में घथाकथित 1 जुलाई, 1997 से हाँगकाँग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के न्यायालयों के गठन में परिवर्तन से इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति के हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[फा. सं. 12(02)/1968-न्या.]

सुरेश चन्द्रा, संयुक्त सचिव और विधिक सलाहकार

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2012

G.S.R. 561(E).— Whereas the Central Government had declared Hong Kong to be a reciprocating territory with effect on and from 1st December, 1968, and the Supreme Court, Victoria District Court, Kowloon District Court and Fanling District Court of Hong Kong as the Superior Courts of Hong Kong for the purpose of section 44 A of Civil Procedure Code (CPC) vide notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Law No.GSR 2096, dated the 18th November, 1968;

AND Whereas, People's Republic of China, upon resumption of the exercise of sovereignty over Hong Kong with effect from 1st July, 1997 under a joint Declaration of the Government of United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the People's Republic of China on the Question of Hong Kong, signed at Beijing on the 19th December, 1984, established the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China;

AND Whereas, the said Declaration stated, inter alia, the Basic policies of the People's Republic of China regarding Hong Kong and elaboration of them in the Annexure I to the said Declaration which has been incorporated in the Basic Law of the Hong Kong Special Administrative Region;

AND Whereas, after the establishment of Hong Kong Special Administrative Region, the independent judicial power in that Region has been vested in the courts of Hong Kong Special Administrative Region and the power of final judgment in the court of Final Appeal (Part III of the Annexure to the said Declaration);

AND Whereas, international agreement to which the People's Republic of China is not a party but which were implemented in Hong Kong may continue to be implemented in the Hong Kong Special Administrative Region (Part IX of the Annexure to the said Declaration);

AND Whereas, the Government of India maintains the existing arrangement for reciprocal enforcement of judgment between India and Hong Kong under section 44 of C.P.C. after the restoration of Hong Kong to the People's Republic of China and establishment of Hong Kong Administrative Region thereafter;

AND Whereas, with establishment of Hong Kong Administrative Region and change in the nomenclature of the Superior Courts of Hong Kong Special Administrative Region, it is expedient to amend the said notification to declare the Hong Kong Special Administrative Region as the reciprocating territory with effect from 1st July, 1997, and new structure of the courts in the Hong Kong Special Administrative Region to facilitate enforcement of the judgment of the Superior Courts of Hong Kong Special Administrative Region in India;

NOW, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Explanation I to section 44 A of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) and in supersession of the Government of India, notification in the erstwhile Ministry of Law (Department of Legal Affairs), notification 2096, dated the 18th November, 1968, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, hereby declares, with effect on and from 1st July, 1997, Hong Kong Special Administrative Region to be reciprocating territory for the purposes of said section and the following Courts in Hong Kong Special Administrative Region to be the Superior Court of that territory, namely:-

1. the Court of Final Appeal (the Highest Appellate Court in Hong Kong Special Administrative Region),

2. the High Court consisting of Court of Appeal, and Court of First Instance, and
3. District Court

Explanatory Memorandum: The change in the set-up of court in Hong Kong Special Administrative Region with effect on and from 1st July 1997, as stated in the Preamble of this notification necessitates the requirement of giving retrospective effect to this notification. It is certified that giving retrospective effect to this notification will not adversely affect the interest of any person.

[F. No. 12(02)/1968-Judl.]

SURESH CHANDRA, Jt. Secy. & Legal Advisor